स्कूल मर्जर का रिव्यू आईआईएम को

ranchi@inext.co.in

RANCHI (20 Dec) : स्कूलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में 4,600 स्कूलों के पास के बड़े स्कूलों में किए गए विलय का मूल्यांकन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (आइआइएम), रांची द्वारा किया जाएगा. राज्य सरकार ने इससे इसमें आनेवाले वित्तीय खर्च का प्रस्ताव मांगा है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नीति आयोग अपने स्तर से इसका मूल्यांकन आइआइएम, बेंगलुरू द्वारा करा रहा है. झारखंड सरकार ने भी आइआइएम, रांची से मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है. पदाधिकारियों ने स्कूलों के विलय के बाद कराए गए आंतरिक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि इससे सात लाख बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा बेहतर वातावरण मिल रहा है, क्योंकि उन्हें आवश्यक संख्या में शिक्षक व अन्य संसाधन मिलने लगे हैं. 96 फीसद बच्चे इससे संतुष्ट हैं. 4,500 शिक्षकों की जरूरत कम हुई है तथा लगभग 400 करोड़ रुपये की बचत हुई है. अधिकारियों के अनुसार, विलय के बाद 150 ऐसे स्कूल चिह्नित किए गए थे जहां के बच्चे पुनर्गठित स्कूल में नहीं जा रहे थे. उनके अभिभावकों की काउंसिलिंग कर उन्हें वापस लाया गया. 90 फीसद बच्चे वापस आ गए. उनके अनुसार, गिने-चुने स्कूल ही हैं जहां बच्चों को परेशानी हो सकती है. उन स्कूलों का विलय रद किया जाएगा.

6,466 स्कूल चिह्नित

शिक्षा सचिव के अनुसार, राज्य सरकार ने दूसरे फेज में पुनर्गठन के लिए 6,466 स्कूलों की पहचान की है, जिनमें सौ से कम बच्चे हैं. इनमें से 411 स्कूलों में दस से कम, 1427 स्कूलों में दस से तीस, 1,894 में 30 से 50 तथा 2,734 स्कूलों में 50 से 100 बच्चे हैं. इनमें 50 से कम बच्चों वाले 3,732 स्कूलों का पहले पुनर्गठन किया जाएगा. पदाधिकारियों के अनुसार, कई याचिकाओं के माध्यम से स्कूलों के पुनर्गठन की चुनौती झारखंड हाईकोर्ट में दी गई थी. हाईकोर्ट ने इनमें से दो याचिकाओं को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

- सरकार का दावा, सात लाख बच्चों को मिलने लगी बेहतर शिक्षा
- स्कूलों के विलय से 400 करोड़ रुपये की हुई बचत
- राज्य भर में कम हुई 4,500 शिक्षकों की जरूरत

पुराने भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र

स्कूलों के विलय के बाद खाली पड़े पुराने भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र, हल्का भवन, पंचायत भवन आदि खोले जाएंगे. भवनों के आवंटन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है.

कक्षा छह-सात के बच्चों को साइकिल

विलय के कारण स्कूलों की दूरी बढ़ने को देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा छह से सात के छात्र-छात्राओं को साइकिल देने का निर्णय लिया है. शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में साइकिल के अलावा अन्य परिवहन या परिवहन भत्ता विकल्प हो सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को साइकिलें ही दी जाएंगी.

केस स्टडी

प्राथमिक उर्दू स्कूल नगड़ी तथा नव प्राथमिक स्कूल भागलपुर का विलय मिडिल स्कूल, नगड़ी में किया गया. दोनों स्कूलों में क्रमशः 16 और 20 बच्चे ही नामांकित थे. दो-दो क्लास रूम तथा एकमात्र शिक्षक थे, जिससे उन्हें पढ़ाने में काफी परेशानी होती थी. विलय के बाद मिडिल स्कूल, नगड़ी में कक्षा एक से आठ तक 650 बच्चे, 27 शिक्षक तथा 18 क्लास रूम हो गए हैं. सभी कक्षाओं में विषयवार शिक्षक मिल गए हैं.

नौनिहालों के भोजन से समझौता नहीं

स्कूलों में बच्चों को परोसे जा रहे मिड डे मील पर उठ रहे सवाल.

मिड डे मील का सच जानने को बनी समिति

22 बिंदुओं पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश

13 शिक्षा अधिकारी एमडीएम का करेंगे इंस्पेक्शन

24 जिलों में घूम कर रिपोर्ट बनाएंगे अधिकारी

30 जनवरी तक प्रधान सचिव के पास रिपोर्ट जमा करने का निर्देश

ranchi@inext.co.in

RANCHI (20 Dec) : मिड डे मील को लेकर अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. राज्य के हर जिले में स्थित सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की क्वालिटी से लेकर उसकी डिलीवरी तक की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है. इसे तैयार करने के लिए 13 अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है. झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की तीसरी बैठक में प्रत्येक माह मॉनिटरिंग का निर्णय लिया गया है. स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के आलोक में एमडीएम के इंस्पेक्शन के लिए जिलावार जिम्मेवारियां बांट दी गई हैं.

चालीस दिनों के भीतर पहली रिपोर्ट

जिन अधिकारियों को इंस्पेक्शन का जिम्मा सौंपा गया है, उन्हें 22 बिंदुओं पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. कुल 13 शिक्षा अधिकारियों को इंस्पेक्शन के लिए 24 जिलों का दायित्व सौंपा गया है. पहला प्रतिवेदन 30 जनवरी को विभाग के प्रधान सचिव के पास जमा करने की हिदायत दी गई है. इंस्पेक्शन करने वालों में निदेशक, प्रशासी पदाधिकारी, आरडीडीई, संयुक्त सचिव समेत अन्य अधिकारी है.

इन बिंदुओं पर बनेगी रिपोर्ट

मिड डे मील का इंस्पेक्शन करने वाले शिक्षा अधिकारियों को 22 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करनी है. इसमें छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, एमडीएम संचालित है या नही, मिन्यू के अनुसार एमडीएम दिया जा रहा है या नही, नोटिस बोर्ड पर मेनू अंकित है या नहीं, रजिस्टर में एमडीएम के स्वाद के बारे में लिखा जाता है या नहीं, किचन शेड, पेयजल, सरस्वती वाहिनी का गठन कब हुआ, एमडीएम का एसएमएस किया जा रहा है या नही और रसोइया का मानदेय भुगतान किस माह तक हुआ है आदि बिंदु हैं

किस जिले का किस अधिकारी करेंगे दौरा

नाम	पद	आवंटित जिला
उमा शंकर सिंह	माध्यमिक निदेशक	रांची व खूंटी
शैलेश कुमार चौरसिया -	अपर सचिव -	धनबाद व गिरिडीह
नारायण विश्वास -	आरडीडीई कोल्हान -	पूर्वी सिंहभूम
विनोद कुमार -	प्रा शिक्षा निदेशक -	रामगढ़ व हजारीबाग
देवेंद्र भूषण सिंह -	संयुक्त सचिव -	लोहरदगा व लातेहार
असीम किस्पोट्टा -	उप सचिव -	पलामू
अशोक कुमार शर्मा -	आरडीडीई रांची -	गुमला
राम जतन राम -	माध्यमिक उप निदेशक -	जामताड़ा व गोड्डा
मुकेश कुमार सिन्हा -	उप निदेशक प्राथमिक -	चतरा व कोडरमा
जयंत कुमार मिश्रा -	प्रशासी पदाधिकारी -	दुमका व साहेबगंज
अरविंद विजय बिलुंग -	आरडीडीई पलामू -	गढ़वा व लातेहार
राजकुमार प्रसाद सिंह -	आरडीडीई दुमका -	पाकुड़ व देवघर